

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह

उप सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

देहरादून दिनांक: 24, फरवरी, 2011

विषय: खरीफ-खरीद मार्केटिंग सत्र 2010-11 में विकेंद्रीकृत योजना के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु स्टेटपूल में कैश क्रेडिट लिमिट/नगद ऋण सीमा की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 47-बीएस/11--2/02 खाद्य/2002 दिनांक 23.02.2011 का सन्म प्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें खरीफ-खरीद सत्र 2010-11 में विकेंद्रीकृत योजना के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु स्टेटपूल के अन्तर्गत राईस मिलर्स से क्रय किये गये धान एवं चावल का पुनर्वातन हेतु कैश क्रेडिट लिमिट/नगद ऋण सीमा की स्वीकृति के संबंध में खाता संख्या-11 के तहत सरकार खरीफ-खरीद हेतु भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, व्यव नियंत्रण विभाग (योजना वित्त-प्रभाग) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अन्तर्गत प्राप्त सहमति के अन्तर्गत वैधता अवधि दिनांक 31 मार्च 2011 तक की नगद ऋण सीमा (सी0सी0एल0) रु0 120.13 करोड़ (रुपये एक सौ बीस करोड़ सौ बीस लाख मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

इस सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक के पत्र संख्या 398/आ0ले0शा0/कैश क्रेडिट लिमिट/2010-11 दिनांक 24.02.2011 में मासान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर उक्त धनराशि का आहरण करने के लिए अपर सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड शासन के अवकाश में होने के कारण अन्य अधिकारी को उक्त औपचारिकतायें सम्पादित किये जाने के निर्देश जारी करने की अपेक्षा की गयी है ताकि सम्बन्धित कैश क्रेडिट लिमिट की धनराशि का आहरण सम्भव किया जा सके।

उक्त के आलोक में जारी शासनादेश दिनांक 23.02.2011 के बिन्दु संख्या-8 में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार देहरादून में कथित स्टेट ग्रेन परचेज एकाउन्ट नामक खाता खोलने से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें अपर सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सम्पादित किये जाने उल्लेख है, के परिपेक्ष्य में शासनादेश के बिन्दु सं0-8 में अपर सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन के स्थान पर कार्यरत में उपसचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन को शासन द्वारा सम्पादित किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। अतः शासनादेश दिनांक 23.02.2011 के बिन्दु संख्या-8 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या 48 B.S / 11-XIX-2/02 खाद्य/2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 नडालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 2 प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 3 वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4 निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, एम0पी0डी0, मुम्बई को फ़ैक्स दिनांक 12.01.2011 के क्रम में।
- 5 सहायक निदेशक, वित्त मंत्रालय, व्यय नियंत्रण विभाग (योजना वित्त-1 प्रभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6 सभागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ/गढ़वाल संभाग, हल्द्वानी/देहरादून।
- 7 जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, चम्पावत, नैनीताल, हरिद्वार एवं पौड़ी।
- 8 सहायक आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल संभाग, हल्द्वानी/देहरादून।
- 9 सभागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, कुमायूँ/गढ़वाल संभाग, हल्द्वानी/देहरादून।
- 10 प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, देहरादून।
- 11 वरिष्ठ कौषाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंह नगर।
- 12 निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
- 13 समन्वयक, एन0आई0सी0, साधेवालय परिसर, देहरादून।
- 14 खाद्य अनुभाग-2 एवं वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 15 गार्ड फ़ाईल।

आइ. अ.

(राजेश सिंह)

उप सचिव।

9.1.11